

# EXAM GENIUS

Presents

# ***GENIUS CURRENT AFFAIRS***

**In Bilingual**

**04 March 2026**



**Achieve Success with Exam Genius - Your Ultimate Guide to Reasoning Mastery !**



**Ques : The Reserve Bank of India has approved SBI Mutual Fund to acquire up to what percentage stake in Bandhan Bank?**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसबीआई म्यूचुअल फंड को बंधन बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण की अनुमति दी है?

- A) 5%
- B) 7.5%
- C) 9.99%
- D) 12%
- E) 15%

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Reserve Bank of India (RBI) has approved a proposal by SBI Mutual Fund to acquire an aggregate holding of up to 9.99% in Bandhan Bank.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एसबीआई म्यूचुअल फंड को बंधन बैंक में कुल मिलाकर 9.99% तक हिस्सेदारी अधिग्रहण की अनुमति दी है।
- The approval is subject to compliance with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949.
- यह अनुमति बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन है।
- SBI Mutual Fund has one year from the date of approval to complete the share acquisition up to the 9.99% limit.
- एसबीआई म्यूचुअल फंड को स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर 9.99% तक शेयर अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।





**Ques : Who has been appointed as the Interim President and Chief Executive Officer (CEO) of the World Economic Forum (WEF)?**

विश्व आर्थिक मंच (WEF) के अंतरिम अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Børge Brende / बोर्जे ब्रेडे
- B) António Guterres / एंतोनियो गुटेरेस
- C) Klaus Schwab / क्लाउस श्वाब
- D) Kristalina Georgieva / क्रिस्टालिना जॉर्जीवा
- E) Alois Zwinggi / अलोइस ज़िविंगी

**Answer: Option E**

**Explanation | व्याख्या:**

- Alois Zwinggi has been appointed as the Interim President and Chief Executive Officer (CEO) of the World Economic Forum (WEF).
- अलोइस ज़िविंगी को विश्व आर्थिक मंच (WEF) का अंतरिम अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है।
- He replaced Børge Brende of Norway.
- उन्होंने नॉर्वे के बोर्जे ब्रेडे का स्थान लिया।
- Alois Zwinggi was earlier appointed as President and CEO of the WEF in 2017.
- अलोइस ज़िविंगी को वर्ष 2017 में भी WEF का अध्यक्ष एवं CEO नियुक्त किया गया था।
- The World Economic Forum (WEF) was established in 1971 and is headquartered in Cologne, Switzerland.
- विश्व आर्थिक मंच (WEF) की स्थापना 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलॉनी, स्विट्जरलैंड में स्थित है।





**Ques : India's 1st State Innovation Mission (SIM) was formally launched in which city?**

भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन (SIM) किस शहर में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया?

- A) Guwahati / गुवाहाटी
- B) Shillong / शिलांग
- C) Agartala / अगरतला
- D) Aizawl / आइजोल
- E) Imphal / इंफाल

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Union Minister of State (Independent Charge) Dr. Jitendra Singh, Ministry of Science and Technology, formally launched India's 1st State Innovation Mission (SIM) at the Hapania International Exhibition Center in Agartala, Tripura.
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने त्रिपुरा के अगरतला स्थित हपनिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में भारत के पहले स्टेट इनोवेशन मिशन (SIM) का शुभारंभ किया।
- The mission is designed as a long-term institutional framework to support States and Union Territories in building robust, inclusive, and context-specific innovation ecosystems aligned with national priorities and local capabilities.
- यह मिशन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं स्थानीय क्षमताओं के अनुरूप मजबूत, समावेशी और संदर्भ-विशिष्ट नवाचार पारितंत्र विकसित करने हेतु एक दीर्घकालिक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है।
- While addressing the event, the Union MoS described the Northeast as the 'New Engine' of India's growth.
- कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर को भारत के विकास का 'नया इंजन' बताया।
- The State Innovation Mission (SIM) is part of the approved Atal Innovation Mission (AIM) 2.0 programme, led by NITI Aayog's State Support Mission (SSM).
- स्टेट इनोवेशन मिशन (SIM) स्वीकृत अटल इनोवेशन मिशन (AIM) 2.0 कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका संचालन नीति आयोग के स्टेट सपोर्ट मिशन (SSM) द्वारा किया जा रहा है।





## Recent News Headlines Related to RBI

**New India Co-operative Bank Limited., Mumbai, Maharashtra has been removed from the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934, which lists scheduled banks in India, effective from February 2026.**

- **Reserve Bank of India (RBI) has issued draft directions allowing AD Category-I banks to undertake Rupee Non-Deliverable Derivative Contracts (NDDCs).**  
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने AD श्रेणी-I बैंकों को रुपये में नॉन-डिलिवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट (NDDCs) करने की अनुमति देने हेतु मसौदा निर्देश जारी किए हैं।
- **The Reserve Bank of India (RBI) has built a high-security data centre in Bhubaneswar, Odisha.**  
• Reserve Bank of India (RBI) ने भुवनेश्वर, ओडिशा में उच्च-सुरक्षा डेटा सेंटर स्थापित किया है।
- **Airtel Money, a subsidiary of Bharti Airtel, has received a Certificate of Registration (CoR) from the Reserve Bank of India to operate as a Type II, non-deposit accepting NBFC.**  
• एयरटेल मनी, जो भारती एयरटेल की सहायक कंपनी है, को भारतीय रिज़र्व बैंक से टाइप II गैर-जमा स्वीकार करने वाली NBFC के रूप में कार्य करने हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।
- **The Reserve Bank of India, in consultation with the Government of India, announced that loans sanctioned by banks to the National Cooperative Development Corporation for on-lending to cooperative societies will be eligible for Priority Sector Lending classification with effect from 19 January 2026.**  
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से यह घोषणा की कि सहकारी समितियों को ऑन-लेंडिंग के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को बैंकों द्वारा दिए गए ऋण 19 जनवरी 2026 से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में मान्य होंगे।
- **The Reserve Bank of India (RBI) has deferred the implementation of the Unique Transaction Identifier (UTI) for all Over-the-Counter (OTC) derivatives to January 1, 2027.**  
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी OTC डेरिवेटिव्स के लिए यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी (UTI) लागू करने की समयसीमा 1 जनवरी 2027 तक बढ़ा दी है।





**Ques :** The “Rah-Veer” scheme, aimed at encouraging citizens to help road accident victims within the golden hour, has been launched in which state/UT?

“राह-वीर” योजना, जो सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन ऑवर के भीतर सहायता देने हेतु नागरिकों को प्रोत्साहित करती है, किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है?

- A) Haryana / हरियाणा
- B) Punjab / पंजाब
- C) Rajasthan / राजस्थान
- D) Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश
- E) Delhi / दिल्ली

**Answer: Option E**

**Explanation | व्याख्या:**

- The “Rah-Veer” scheme has been announced by Delhi Chief Minister Rekha Gupta.
- “राह-वीर” योजना की घोषणा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा की गई है।
- Under the scheme, any person who helps a seriously injured road accident victim and ensures their transport to a hospital or trauma centre within the golden hour will receive Rs. 25,000 as a cash reward along with a certificate of appreciation.
- इस योजना के अंतर्गत, जो भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल सड़क दुर्घटना पीड़ित को गोल्डन ऑवर के भीतर अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाने में सहायता करेगा, उसे ₹25,000 की नकद राशि और प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- A maximum of Rs. 25,000 per incident will be provided even if multiple victims are saved in the same incident.
- एक ही घटना में यदि कई पीड़ितों को बचाया जाता है, तब भी अधिकतम ₹25,000 प्रति घटना प्रदान किए जाएंगे।
- Ten outstanding “Rah-Veers” selected nationally each year will receive a special award of Rs. 1 lakh along with a certificate.
- प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर चयनित 10 उत्कृष्ट “राह-वीरों” को ₹1 लाख की विशेष पुरस्कार राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।





**Ques : The Rail Tech Policy and complete digitisation of the Railway Claims Tribunal (RCT) are part of which initiative of Indian Railways?**

रेल टेक नीति और रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल (RCT) का पूर्ण डिजिटलीकरण भारतीय रेल की किस पहल का हिस्सा है?

- A) Digital India Mission / डिजिटल इंडिया मिशन
- B) Gati Shakti Programme / गति शक्ति कार्यक्रम
- C) National Rail Plan 2030 / नेशनल रेल प्लान 2030
- D) 52 Reforms in 52 Weeks / 52 सप्ताह में 52 सुधार
- E) Make in India / मेक इन इंडिया

**Answer: Option D**

**Explanation | व्याख्या:**

- Union Minister Ashwini Vaishnaw announced the launch of the Rail Tech Policy and the complete digitisation of the Railway Claims Tribunal (RCT).
- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल टेक नीति और रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल (RCT) के पूर्ण डिजिटलीकरण की घोषणा की।
- These are Reform Number Three and Reform Number Four under Indian Railways' flagship '52 Reforms in 52 Weeks' initiative.
- ये भारतीय रेल की प्रमुख पहल '52 सप्ताह में 52 सुधार' के तहत क्रमशः सुधार संख्या तीन और सुधार संख्या चार हैं।
- A dedicated RailTech Portal will be launched to enable innovators to submit proposals through a fully digital, end-to-end process.
- एक समर्पित रेलटेक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिससे नवाचारकर्ता पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे।
- Anyone with a strong technological idea can approach the Railways through the RailTech Portal to enable systematic induction of technology into the Railways.
- कोई भी व्यक्ति मजबूत तकनीकी विचार के साथ रेलटेक पोर्टल के माध्यम से रेलवे से संपर्क कर सकता है, जिससे रेलवे में व्यवस्थित रूप से नई तकनीक का समावेशन हो सके।
- The Railways will fund up to 50% of development costs for viable solutions and place large-scale orders for successful innovations.
- रेलवे व्यवहार्य समाधानों के विकास लागत का 50% तक वित्तपोषण करेगा और सफल नवाचारों के लिए बड़े





पैमाने पर ऑर्डर देगा।

- Under the major procedural reform in RCT, 24×7 e-filing, online hearings, and instant access to orders will simplify accident and untoward incident claims for litigants.
- RCT में बड़े प्रक्रियात्मक सुधार के तहत 24×7 ई-फाइलिंग, ऑनलाइन सुनवाई और आदेशों की त्वरित उपलब्धता से दुर्घटना एवं अन्य दावों की प्रक्रिया आसान होगी।



EXAM  
Genius





## Recent Appointment in different departments :

- **Deepak Gupta : Chairman & Managing Director (CMD) of GAIL (India) Limited (replaced Sandeep Kumar Gupta)**  
• दीपक गुप्ता : गेल (इंडिया) लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) का पदभार ग्रहण किया। (संदीप कुमार गुप्ता का स्थान लिया)
- **Senior bureaucrat Nidhi Chibber : Chief Executive Officer (CEO) of NITI Aayog**  
• वरिष्ठ नौकरशाह निधि चिबबर: नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)
- **Ajay Kapur : Group CEO of Suzlon Energy**  
• अजय कपूर: सुजलॉन एनर्जी के ग्रुप सीईओ
- **Asha Sharma : CEO of Microsoft Gaming (Replaced Phil Spencer)**  
• आशा शर्मा: माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की सीईओ (फिल स्पेंसर की जगह ली)
- **Uday Kotak : Chairman of Gujarat International Finance Tec-City Company Ltd (GIFT City). (Replaced Hasmukh Adhia (From June 2023))**  
• उदय कोटक: गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कंपनी लिमिटेड (गिफ्ट सिटी) के अध्यक्ष। (हसमुख अधिया का स्थान लिया गया (जून 2023 से))
- **Rohit Kumar Singh, former Consumer Affairs Secretary : Chair of the Global Value Chains Committee of the US-India Strategic Partnership Forum (USISPF)**  
• रोहित कुमार सिंह, पूर्व उपभोक्ता मामलों के सचिव : यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसएफ) की ग्लोबल वैल्यू चेन कमेटी के अध्यक्ष
- **Prasanna Kumar D : President of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) for the 2026-27 term. (Replaced CA Charanjot Singh Nanda)**  
• प्रसन्न कुमार डी : 2026-27 कार्यकाल के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया (सीए चरणजोत सिंह नंदा की जगह ली)
- **Deepak Gupta : Chairman & Managing Director (CMD) of GAIL (India) Limited (Replace Sandeep Kumar Gupta)**





**Ques: The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) Raebareli signed an MoU with which company to strengthen pharmaceutical education and innovation-driven drug development?**

राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (NIPER), रायबरेली ने औषधि शिक्षा एवं नवाचार आधारित दवा विकास को सुदृढ़ करने हेतु किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए?

- A) Pfizer India / फाइजर इंडिया
- B) Cipla Limited / सिप्ला लिमिटेड
- C) Boehringer Ingelheim India Private Limited / बोहरिंगर इंगेलहाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- D) Sun Pharmaceutical Industries / सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज
- E) Dr. Reddy's Laboratories / डॉ. रेड्डीज लैबोरेट्रीज

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

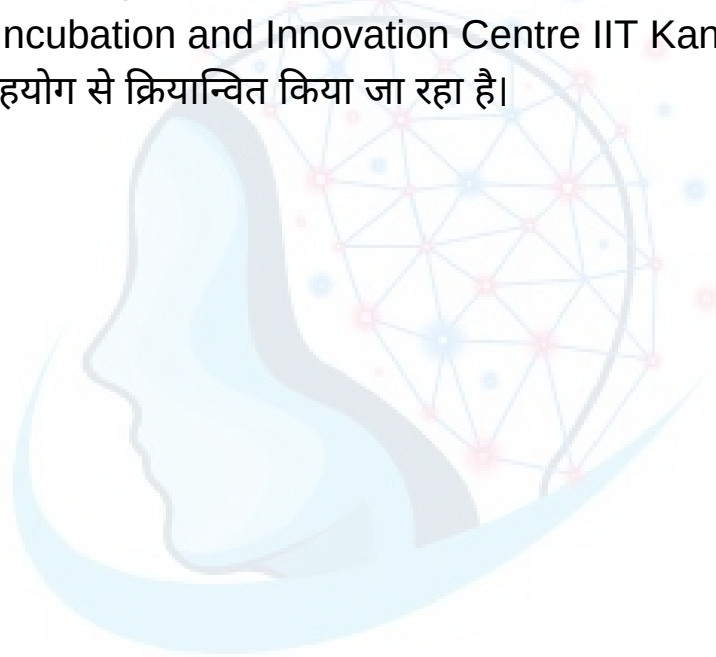
- National Institute of Pharmaceutical Education and Research Raebareli (NIPER), Uttar Pradesh, along with its Centre of Excellence for Novel Drug Delivery Systems (CoE-NDDS), signed an MoU with Boehringer Ingelheim India Private Limited.
- National Institute of Pharmaceutical Education and Research Raebareli (NIPER), उत्तर प्रदेश ने अपने Centre of Excellence for Novel Drug Delivery Systems (CoE-NDDS) के साथ मिलकर Boehringer Ingelheim India Private Limited के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- The collaboration aims to strengthen pharmaceutical education, research collaboration, and innovation-driven drug development in India.
- इस सहयोग का उद्देश्य भारत में औषधि शिक्षा, अनुसंधान सहयोग तथा नवाचार आधारित दवा विकास को सुदृढ़ करना है।
- During the event, Cohort-2 of AMRITVA (Alliance for Medical Research, Innovation, Translation & Value Acceleration) was launched to accelerate medical research translation and commercialization.
- इस अवसर पर AMRITVA (Alliance for Medical Research, Innovation, Translation & Value Acceleration) के Cohort-2 का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य चिकित्सा अनुसंधान के रूपांतरण एवं व्यावसायीकरण को तेज करना है।
- A total of 5 innovators were selected, including 3 faculty-led projects and 2 research





scholar-led projects.

- कुल 5 नवोन्मेषकों का चयन किया गया, जिनमें 3 संकाय-नेतृत्व वाले प्रोजेक्ट और 2 शोधार्थी-नेतृत्व वाले प्रोजेक्ट शामिल हैं।
- Selected innovators will receive grant support for commercialization of research outcomes.
- चयनित नवोन्मेषकों को अनुसंधान परिणामों के व्यावसायीकरण हेतु अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी।
- AMRITVA is implemented by Startup Incubation and Innovation Centre IIT Kanpur (SIIC-IIT Kanpur) in partnership with NIPER Raebareli.
- AMRITVA को Startup Incubation and Innovation Centre IIT Kanpur (SIIC-IIT कानपुर) द्वारा NIPER रायबरेली के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है।



EXAM  
Genius





**Ques : The 'Meri Rasoi' scheme, recently launched, has been introduced by which state government?**

'मेरी रसोई' योजना, हाल ही में शुरू की गई, किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है?

- A) Punjab / पंजाब
- B) Rajasthan / राजस्थान
- C) Haryana / हरियाणा
- D) Himachal Pradesh / हिमाचल प्रदेश
- E) Uttarakhand / उत्तराखंड

**Answer: Option A**

**Explanation | व्याख्या:**

- The 'Meri Rasoi' scheme has been launched by the Punjab government.
- 'मेरी रसोई' योजना पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई है।
- The objective of the scheme is to provide nutritional support to nearly 40 lakh economically weaker families across the state.
- इस योजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 40 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है।
- Under this scheme, food kits will be distributed free of cost for three months at a time.
- इस योजना के तहत खाद्य किट तीन-तीन महीने की अवधि के लिए निःशुल्क वितरित की जाएंगी।
- The first phase will cover April, May and June 2026.
- इसका पहला चरण अप्रैल, मई और जून 2026 को कवर करेगा।

**Each eligible family will receive: / प्रत्येक पात्र परिवार को निम्नलिखित सामग्री प्राप्त होगी:**

- 2 kilogram chana dal / 2 किलोग्राम चना दाल
- 2 kilogram sugar / 2 किलोग्राम चीनी
- 1 kilogram iodized salt / 1 किलोग्राम आयोडीन युक्त नमक
- 200 gram turmeric powder / 200 ग्राम हल्दी पाउडर
- 1 litre mustard oil / 1 लीटर सरसों का तेल





## News Headlines Related to Ministry :

• **Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupender Yadav announced the arrival of nine cheetahs from Botswana.**

• केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बोत्सवाना से 9 चीतों के आगमन की घोषणा की।

**The Science and Technology Minister announced the establishment of “Bio-AI Mulankur” hubs to create integrated, closed-loop research platforms. The initiative aligns with the BioE3 Policy (Biotechnology for Environment, Economy and Employment)**

• **The Ministry of Minority Affairs (MoMA) organized ‘Chintan Shivir’, a strategic platform to review and strengthen minority welfare policies and programmes.**

• अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MoMA) ने ‘चिंतन शिविर’ का आयोजन किया, जो अल्पसंख्यक कल्याण नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा एवं सुदृढीकरण हेतु एक रणनीतिक मंच है।

• **The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has constituted a high-level committee to review and improve rules related to DigiLocker.**

• इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने DigiLocker से जुड़े नियमों की समीक्षा और सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।

• **Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) is organising ‘Him-CONNECT’ as part of the World Sustainable Development Summit (WSDS) 2026.**

• पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट (WSDS) 2026 के अंतर्गत ‘हिम-कनेक्ट’ का आयोजन किया जा रहा है।

• **The Ministry of Home Affairs (MHA) has released India’s first-ever National Counter Terrorism Policy and Strategy titled PRAHAAR.**

• Ministry of Home Affairs (MHA) ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति ‘PRAHAAR’ जारी की है।





**Ques : The National Small Industries Corporation Limited (NSIC) has been upgraded to which category of Central Public Sector Enterprise (CPSE)?**

नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NSIC) को किस श्रेणी के केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (CPSE) में उन्नत किया गया है?

- A) Schedule 'A' / शेड्यूल 'A'
- B) Schedule 'B' / शेड्यूल 'B'
- C) Schedule 'C' / शेड्यूल 'C'
- D) Schedule 'D' / शेड्यूल 'D'
- E) Maharatna Category / महारत्न श्रेणी

**Answer: Option A**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MoMSME) has upgraded the National Small Industries Corporation Limited (NSIC) from Schedule 'B' to Schedule 'A' category CPSE.
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) ने नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NSIC) को शेड्यूल 'B' से शेड्यूल 'A' श्रेणी के केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम में उन्नत किया है।
- Schedule 'A' status provides NSIC greater financial and operational autonomy.
- शेड्यूल 'A' का दर्जा NSIC को अधिक वित्तीय एवं परिचालन स्वायत्तता प्रदान करता है।
- This upgrade will strengthen NSIC's role in implementing Government of India programmes.
- यह उन्नयन भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में NSIC की भूमिका को सुदृढ़ करेगा।
- The Department of Public Enterprises (DPE) classifies CPSEs into four schedules: A, B, C, and D to streamline management and salary structures.
- लोक उद्यम विभाग (DPE) प्रबंधन और वेतन संरचना को सुव्यवस्थित करने हेतु CPSEs को चार श्रेणियों—A, B, C और D—में वर्गीकृत करता है।





**Ques: The Union Government has introduced a national Access Pass system to promote sustainable fishing within which maritime zone?**

केंद्र सरकार ने सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु किस समुद्री क्षेत्र के भीतर राष्ट्रीय एक्सेस पास प्रणाली शुरू की है?

- A) Territorial Sea / प्रादेशिक सागर
- B) Contiguous Zone / संलग्न क्षेत्र
- C) Exclusive Economic Zone (EEZ) / विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ)
- D) High Seas / उच्च समुद्र
- E) Continental Shelf / महाद्वीपीय शेल्फ

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

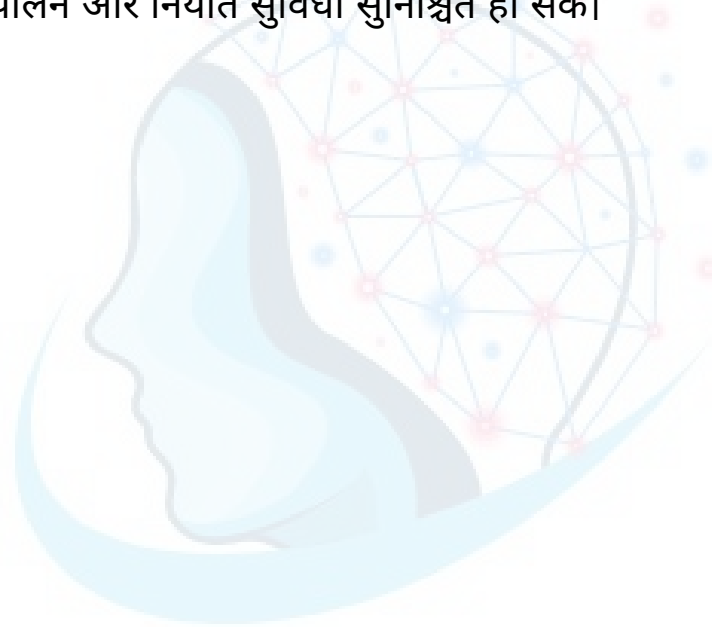
- The Union Government has introduced a national Access Pass system to encourage sustainable fishing within India's Exclusive Economic Zone (EEZ).
- केंद्र सरकार ने भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एक्सेस पास प्रणाली शुरू की है।
- The EEZ is a maritime zone that extends up to 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.
- EEZ वह समुद्री क्षेत्र है जो प्रादेशिक सागर की चौड़ाई मापने वाली आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक विस्तारित होता है।
- Under the EEZ Rules, the Access Pass aims to promote the transition towards deep-sea fishing and encourage the formation of Fisheries Cooperatives and Fishermen Fish Producer Organisations (FFPOs).
- EEZ नियमों के तहत, एक्सेस पास का उद्देश्य गहरे समुद्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और मत्स्य सहकारी समितियों तथा फिश प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस (FFPOs) के गठन को प्रोत्साहित करना है।
- The pass is mandatory for approximately 64,000 mechanised vessels and large motorised vessels above 24 metres, while traditional non-motorised or artisanal fishers are exempted.
- यह पास लगभग 64,000 यांत्रिक नौकाओं और 24 मीटर से अधिक लंबाई वाले मोटर चालित जहाजों के लिए अनिवार्य है, जबकि पारंपरिक गैर-मोटर चालित या कारीगर मछुआरे इससे मुक्त हैं।
- The pass is issued free of cost through the ReALCRaft digital platform, developed by





the National Informatics Centre and the Department of Fisheries.

- यह पास ReALCRaft डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निःशुल्क जारी किया जाता है, जिसे National Informatics Centre और Department of Fisheries द्वारा विकसित किया गया है।
- ReALCRaft is integrated with the Marine Products Export Development Authority (MPEDA) for Catch Certificates and the Export Inspection Council (EIC) for Health Certificates to ensure regulatory compliance and export facilitation.
- ReALCRaft को Marine Products Export Development Authority (MPEDA) के साथ कैच सर्टिफिकेट हेतु तथा Export Inspection Council (EIC) के साथ हेल्थ सर्टिफिकेट हेतु एकीकृत किया गया है, जिससे नियामक अनुपालन और निर्यात सुविधा सुनिश्चित हो सके।



EXAM  
Genius





**Ques : Mount Aconcagua, recently summited by a six-member Indian team, is located in which country?**

हाल ही में छह सदस्यीय भारतीय दल द्वारा आरोहित माउंट अकोंकागुआ किस देश में स्थित है?

- A) Argentina / अर्जेटीना
- B) Peru / पेरू
- C) Chile / चिली
- D) Bolivia / बोलिविया
- E) Ecuador / इक्वाडोर

**Answer: Option A**

**Explanation | व्याख्या:**

- A six-member team from the Nehru Institute of Mountaineering (NIM), Uttarkashi, Uttarakhand and the Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports (JIM&WS), Pahalgam, Jammu & Kashmir, successfully summited Mount Aconcagua in Argentina.
- उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग (NIM) तथा जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स (JIM&WS) की छह सदस्यीय टीम ने अर्जेटीना में माउंट अकोंकागुआ पर सफलतापूर्वक आरोहण किया।
- The expedition was formally flagged off by Union Minister Rajnath Singh, Ministry of Defence (MoD).
- इस अभियान को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई।
- The expedition team was led by Colonel Hem Chandra Singh, Principal of NIM and JIM&WS.
- इस अभियान का नेतृत्व कर्नल हेम चंद्र सिंह, जो NIM और JIM&WS के प्राचार्य हैं, ने किया।
- Mount Aconcagua is the highest peak in South America.
- माउंट अकोंकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी है।





## Recent News Headlines Related to Schemes

- The scheme 'Banglar Yuva Sathi' has been launched by Mamata Banerjee, Chief Minister of West Bengal.  
• 'बांग्लार युवा साथी' योजना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई है।
- The Government of India has launched the PM RAHAT (Road Accident Victim Hospitalization and Assured Treatment) Scheme from the Prime Ministerial office, Seva Teerth.  
• भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय, सेवा तीर्थ से पीएम राहत (Road Accident Victim Hospitalization and Assured Treatment) योजना शुरू की है।
- The Chief Minister of Kerala, Pinarayi Vijayan, launched the 'Sthree Suraksha Scheme'.  
• केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 'स्त्री सुरक्षा योजना' की शुरुआत की।
- The Delhi Lakhpati Bitiya Yojana has replaced the Delhi Ladli Scheme (2008) and supports girls from birth to graduation.  
• दिल्ली लखपति बिटिया योजना ने 2008 की दिल्ली लाडली योजना की जगह ली है और जन्म से स्नातक तक बालिकाओं को सहायता देती है।
- The Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) approved the construction of over 3.53 lakh houses under Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban 2.0 (PMAY-U 2.0).  
• आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत 3.53 लाख से अधिक घरों के निर्माण को मंजूरी दी।
- The Ministry of Parliamentary Affairs unveiled the upgraded National Youth Parliament Scheme (NYPS 2.0) web portal to significantly expand the reach and inclusivity of the Youth Parliament Programme across India.  
• संसदीय कार्य मंत्रालय ने यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम की पहुँच और समावेशन बढ़ाने के लिए नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम (NYPS 2.0) का उन्नत वेब पोर्टल लॉन्च किया।
- Mukhyamantri Gramotthan Yojana (MGY) was launched by Bhupendra Patel, the Chief Minister of Gujarat.





**Ques: The Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) has launched which initiative to monitor the quality of ongoing National Highway (NH) projects across India?**

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने देशभर में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) परियोजनाओं की गुणवत्ता की निगरानी हेतु कौन-सी पहल शुरू की है?

- A) National Highway Expansion Mission / राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार मिशन
- B) Mobile Quality Control Vans (MQCVs) Initiative / मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन पहल
- C) Bharat Highway Acceleration Project / भारत हाईवे त्वरित परियोजना
- D) Smart Toll Monitoring Scheme / स्मार्ट टोल निगरानी योजना
- E) Green Corridor Development Programme / ग्रीन कॉरिडोर विकास कार्यक्रम

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) has launched a new initiative introducing Mobile Quality Control Vans (MQCVs) to diagnose and monitor the quality of ongoing National Highway projects across India.
- Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) ने देशभर में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता की जांच और निगरानी के लिए मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन (MQCVs) पहल शुरू की है।
- The move reflects a shift from rapid road expansion towards ensuring high-quality, safe and reliable highway infrastructure.
- यह कदम तीव्र सड़क विस्तार से ध्यान हटाकर उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित और विश्वसनीय राजमार्ग अवसंरचना सुनिश्चित करने की दिशा में बदलाव को दर्शाता है।
- Pilot projects have been implemented in Rajasthan, Gujarat, Karnataka and Odisha to test the effectiveness of advanced quality monitoring systems.
- उन्नत गुणवत्ता निगरानी प्रणालियों की प्रभावशीलता जांचने के लिए राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा में पायलट परियोजनाएं लागू की गई हैं।
- The MQCVs operate as mobile laboratories conducting on-site and real-time testing of highway construction quality using non-destructive testing technologies.
- MQCVs मोबाइल प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करती हैं, जो गैर-विनाशकारी परीक्षण तकनीकों के माध्यम से राजमार्ग निर्माण की गुणवत्ता की ऑन-साइट और रीयल-टाइम जांच करती हैं।







**Ques : Where was the 4th World Ocean Science Congress 2026 held?**

चौथा विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया?

- A) Visakhapatnam / विशाखापत्तनम
- B) Kochi / कोच्चि
- C) Panaji, Goa / पणजी, गोवा
- D) Chennai / चेन्नई
- E) Mumbai / मुंबई

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- The 4th edition of the World Ocean Science Congress 2026 was held at the National Institute of Oceanography in Panaji, Goa.
- विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन 2026 का चौथा संस्करण पणजी, गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी में आयोजित किया गया।
- The Congress is organised biannually.
- यह सम्मेलन द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है।
- Theme: "Ocean Health and Sustainable Future"
- विषय: "महासागर का स्वास्थ्य और सतत भविष्य"
- It was organised by the National Institute of Oceanography (NIO), the National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR), and Goa University.
- इसका आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO), नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (NCPOR) तथा गोवा विश्वविद्यालय द्वारा किया गया।
- Previous editions were held in Visakhapatnam, Kochi, and Chennai.
- इसके पूर्व संस्करण विशाखापत्तनम, कोच्चि और चेन्नई में आयोजित किए गए थे।





## Recent News Headlines Related to MoU and agreement:

- **Unique Identification Authority of India (UIDAI) and Google signed MOU to enable the display of authorised Aadhaar centres on Google Maps, a move that will enhance ease of access and convenience for residents across the country**  
• भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) और गूगल ने गूगल मैप्स पर अधिकृत आधार केंद्रों को प्रदर्शित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम देशभर के निवासियों के लिए पहुंच को आसान और सुविधाजनक बनाएगा।
- **GalaxEye, an IIT-Madras incubated startup, has officially partnered with NewSpace India Limited (NSIL), the commercial arm of ISRO. Under this agreement, NSIL will act as a global reseller for GalaxEye's highresolution satellite imagery.**  
• IIT-मद्रास द्वारा विकसित स्टार्टअप गैलेक्सीआई ने ISRO की वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के साथ आधिकारिक तौर पर साझेदारी की है। इस समझौते के तहत, NSIL गैलेक्सीआई की उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह छवियों के वैश्विक पुनर्विक्रेता के रूप में कार्य करेगा।
- **India's Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) and Nepal's Ministry of Forests and Environment signed a MOU to strengthen the bilateral cooperation in protecting shared ecosystems and restoring transboundary wildlife corridors. Key species identified under the pact are Elephant, Gangetic dolphin, Rhinoceros, Snow leopard, Tiger and Vultures**  
• भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) और नेपाल के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने साझा पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा और सीमा पार वन्यजीव गलियारों के पुनर्स्थापन में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत जिन प्रमुख प्रजातियों की पहचान की गई है, वे हैं हाथी, गंगा डॉल्फिन, गैंडा, हिम तेंदुआ, बाघ और गिद्ध।
- **India signed an Implementation Framework Agreement with Kenya to launch a DigiLocker pilot project. Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) launched DigiLocker as a flagship initiative under the Digital India programme**  
• भारत ने केन्या के साथ एक कार्यान्वयन ढांचा समझौता (Implementation Framework Agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत डिजीलॉकर पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख पहल के रूप में डिजीलॉकर लॉन्च किया है।





**Ques : Teacher App 2.0, aimed at accelerating AI adoption in India's K-12 ecosystem, was launched by whom?**

भारत के के-12 शिक्षा तंत्र में एआई अपनाने को बढ़ावा देने हेतु टीचर ऐप 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया?

- A) Ashwini Vaishnaw / अश्विनी वैष्णव
- B) Dharmendra Pradhan / धर्मेंद्र प्रधान
- C) Jitendra Singh / जितेंद्र सिंह
- D) Nirmala Sitharaman / निर्मला सीतारमण
- E) Rajnath Singh / राजनाथ सिंह

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- Teacher App 2.0 was launched by Union Minister of Education Dharmendra Pradhan.
- टीचर ऐप 2.0 का शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया।
- The app has been developed by Bharti Airtel Foundation in collaboration with CK-12 Foundation.
- यह ऐप भारती एयरटेल फाउंडेशन द्वारा CK-12 फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है।
- Its objective is to accelerate Artificial Intelligence (AI) adoption in India's K-12 (Kindergarten to Class 12) ecosystem.
- इसका उद्देश्य भारत के के-12 (किंडरगार्टन से कक्षा 12 तक) शिक्षा तंत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को बढ़ावा देना है।
- The initiative is aligned with the National Education Policy (NEP) 2020 and Viksit Bharat @2047 vision.
- यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 तथा विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- The app currently supports over two lakh educators across India and is available as a free-for-life digital platform.
- यह ऐप वर्तमान में भारत भर में दो लाख से अधिक शिक्षकों को सहयोग प्रदान कर रहा है और आजीवन निःशुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में उपलब्ध है।





**Ques: The Government of India has reduced duty benefits under which export support scheme by 50% with immediate effect?**

भारत सरकार ने किस निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत शुल्क लाभ को तत्काल प्रभाव से 50% घटा दिया है?

- A) MEIS (Merchandise Exports from India Scheme) / भारत से माल निर्यात योजना
- B) SEIS (Service Exports from India Scheme) / सेवा निर्यात योजना
- C) RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) / निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की वापसी योजना
- D) EPCG (Export Promotion Capital Goods) / निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत वस्तु योजना
- E) PLI (Production Linked Incentive) / उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Government of India has reduced duty benefits under the RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) scheme by 50% with immediate effect.
- भारत सरकार ने RoDTEP (निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की वापसी योजना) के तहत शुल्क लाभ को तत्काल प्रभाव से 50% घटा दिया है।
- The decision was notified by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT), raising concerns among exporters.
- यह निर्णय Directorate General of Foreign Trade (DGFT) द्वारा अधिसूचित किया गया, जिससे निर्यातकों के बीच चिंता उत्पन्न हुई है।
- The RoDTEP scheme was launched in 2021 to support Indian exporters by refunding taxes, duties, and levies incurred during manufacturing, transportation, and distribution of export goods.
- RoDTEP योजना वर्ष 2021 में भारतीय निर्यातकों को समर्थन देने के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत निर्माण, परिवहन एवं वितरण के दौरान लगे करों और शुल्कों की वापसी की जाती है।
- These costs are those not reimbursed under any other central, state, or local mechanism.
- ये वे लागतें हैं जिनकी प्रतिपूर्ति किसी अन्य केंद्रीय, राज्य या स्थानीय तंत्र के अंतर्गत नहीं की जाती है।
- Under the new change, RoDTEP benefits are now restricted to 50% of the existing notified rates, and value caps have also been reduced by 50%.
- नए परिवर्तन के तहत, RoDTEP के लाभ अब पूर्व अधिसूचित दरों के 50% तक सीमित कर दिए गए हैं





**Ques :** The “CM Jan Sunwai Portal & Mobile App”, a centralised grievance redressal system, has been launched in which state/UT?

“सीएम जन सुनवाई पोर्टल एवं मोबाइल ऐप”, एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली, किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है?

- A) Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश
- B) Delhiyly
- C) Delhi / दिल्ली
- D) Haryana / हरियाणा
- E) Punjab / पंजाब

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- The initiatives were launched by Delhi Chief Minister Rekha Gupta at the Delhi Secretariat, New Delhi.
- इन पहलों का शुभारंभ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा नई दिल्ली स्थित दिल्ली सचिवालय में किया गया।
- The objective is to strengthen digital public service delivery and citizen grievance redressal through IT-based governance initiatives.
- इसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शासन पहलों के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक सेवा वितरण एवं नागरिक शिकायत निवारण को सुदृढ़ करना है।

**Major Initiatives Launched | प्रमुख पहलें:**

**1. CM Jan Sunwai Portal & Mobile App:**

A centralised grievance redressal system enabling citizens to submit complaints across departments.

यह एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसके माध्यम से नागरिक विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।

**2. Integration of e-District Services with Common Service Centre (CSC) Network:**

To enhance accessibility of government services at the grassroots level.

जमीनी स्तर पर सरकारी सेवाओं की पहुँच बढ़ाने हेतु ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)





नेटवर्क से जोड़ा गया है।

### 3. Secure Online Admission Platform:

To ensure transparent and secure digital admission processes.

पारदर्शी और सुरक्षित डिजिटल प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षित ऑनलाइन प्रवेश मंच विकसित किया गया है।



EXAM  
Genius





## Recent News Headlines Related to Summits / conference

**At the India AI Impact Summit 2026 held in New Delhi, Reliance Industries Chairman Mukesh Ambani announced a ₹10 trillion investment in Artificial Intelligence over the next seven years.**

- **The 5th edition of the Goa Maritime Conclave (GMC-26) will be held on 21 February 2026 at the Naval War College, Goa.**  
• गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव (GMC-26) का 5वां संस्करण 21 फरवरी 2026 को गोवा स्थित नौसेना युद्ध महाविद्यालय में आयोजित किया जाएगा।
- **The third International AYUSH Conference and Expo concluded at the Dubai World Trade Centre.**  
• तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं एक्सपो दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में संपन्न हुआ।
- **RISE (Research–Industry–Startup–Entrepreneurship) Conclave 2026 was organized to bridge the gap between laboratory research and market needs by bringing together researchers, industry leaders, academia, and startups.**  
• RISE (रिसर्च–इंडस्ट्री–स्टार्टअप–एंटरप्रेन्योरशिप) कॉन्क्लेव 2026 का उद्देश्य प्रयोगशाला अनुसंधान और बाजार की जरूरतों के बीच की खाई को पाटना था।
- **India attended the first Board of Peace for Gaza meeting in Washington, D.C. as an observer.**  
• भारत ने वाशिंगटन डी.सी. में आयोजित गाजा के लिए पहली Board of Peace बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया।
- **Union Minister of Health & Family Welfare J. P. Nadda will launch two major national initiatives at the India AI Summit held at Bharat Mandapam.**  
• केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI समिट में दो प्रमुख राष्ट्रीय पहलों का शुभारंभ करेंगे।
- **Guy Parmelin, President of Switzerland, announced that the 2027 AI Impact Summit will be held in Geneva.**  
• स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन ने घोषणा की कि 2027 AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन जिनेवा में होगा।





## Recent News Headlines Related to launched Apps/portals :

- **The Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sarma, launched the Provincialization Management System (PMS) portal.**  
• असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रोविंशियलाइज़ेशन मैनेजमेंट सिस्टम (PMS) पोर्टल लॉन्च किया।
- **Kiren Rijju, Union Minister of Ministry of Minority Affairs, launched the NIGRANI App at Nalanda University, Bihar.**  
• अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री किरण रिजजू ने बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में NIGRANI ऐप लॉन्च किया।
- **Indian Army showcased 'EKAM', an indigenous AI-as-a-Service (AlaaS) cloud platform.**  
• भारतीय सेना ने 'EKAM' नामक स्वदेशी AI-as-a-Service क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया।
- **India launched iLive Connect, the world's first doctor-led, Artificial Intelligence (AI) powered healthcare ecosystem, aimed at providing 24x7 medical monitoring from patients' homes.**  
• भारत ने iLive Connect लॉन्च किया है, जो दुनिया का पहला डॉक्टर-नेतृत्व वाला एआई-संचालित हेल्थकेयर इकोसिस्टम है, जिसका उद्देश्य मरीजों को उनके घर से ही 24x7 चिकित्सा निगरानी प्रदान करना है।
- **Jitin Prasada, Minister of State for Electronics and Information Technology, inaugurated the STQC Lab Automation Portal named 'SATYA'.**  
• इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने 'SATYA' नामक STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल का उद्घाटन किया।
- **From March 1, 2026, the UTS (Unreserved Ticketing System) mobile app will be discontinued, and passengers must use the RailOne super app for ticket booking.**  
• 1 मार्च 2026 से UTS (अनारक्षित टिकट प्रणाली) मोबाइल ऐप को बंद कर दिया जाएगा और यात्रियों को टिकट बुकिंग के लिए RailOne सुपर ऐप का उपयोग करना होगा।
- **Om Birla, Speaker of the Lok Sabha (Lower House of Parliament), launched the National e-Vidhan Application (NeVA) at the Central Hall of the Bihar State Legislative Assembly in Patna.**

